पाकिस्तान में अल्पसंख्यक निशाने पर

-अरविंद जयतिलक

पाकिस्तान के पेशावर में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आर्तकियों ने पिछले दिनों शिया मस्जिद में आत्मघाती हमलाकर एक बार फिर अपने कायराना कृत्य को अंजाम दिया है। इस हमले में दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। आर्तकियों ने यह बर्बर कृत्य उस समय किया जब लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से फिर साबित हुआ है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय समेत कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। अभी चंद सप्ताह पहले ही आर्तकियों ने सिंध प्रांत में जुमे की नमाज की दौरान शिया मस्जिद में ही हमलाकर पांच दर्जन से अधिक लोगों की जान ली। गौर करें तो यह पहली बार नहीं है जब आर्तकियों ने शिया समुदाय को निशाने पर लिया हो। सच तो यह है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय भी उतना ही असुरक्षित और भयग्रस्त है जितना कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय। पाकिस्तान ही नहीं, आज दुनिया भर में शिया समुदाय सुन्नी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इसकी गूंज लेबनान से सीरिया और इराक से पाकिस्तान तक सुनी जा सकती है। रही बात पाकिस्तान की तो यहां शिया ही नहीं ईसाई, हिंदू व सिख समुदाय भी असुरक्षित हैं। याद होगा चंद माह पहले आर्तकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के चर्च व्हाइट-स्टोन ऑल सेंट को निशाना बना सैकड़ों की जान ली थी। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान का धड़ा जनदुल्ला ने ली और कहा कि यह हमला अमेरिकी ड्रोन हमलों का बदला है और वे तब गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाते रहेंगे जब तक कि अमेरिका ड्रोन हमले बंद नहीं होते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या 1.6 फीसदी है और दिनोंदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक, आर्तकियों का डर और दूसरा उनका जबरन धर्मांतरण। धर्मांतरण का विरोध करने पर उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाता है। याद होगा अभी दो वर्ष पहले ही पाकिस्तान के गोजरा में 1000 कट्टरपंथियों ने ईसाई घरों पर हमला बोल 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस तरह की बर्बर घटनाएं पाकिस्तान में आम हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के लिए सिर्फ आतंकी समूह ही नहीं बल्कि सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां विशेष रूप से निंदा कानून भी जिम्मेदार है। कहीं आतंकी नाराज न हो जाएं इस भय से सरकार इस कानून को नहीं हटा रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को हाशिए पर डाल दिया है। गत वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी स्कूलों की किताबें अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। मजहबी शिक्षक धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस्लाम के शत्रु की तरह पेश करते हैं। उन्हें काफिर बता मुस्लिम बच्चों के मन में जहर घोलते हैं। रिपोर्ट में यह भी उद्घाटित हुआ है कि पाकिस्तान में सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भारत और ब्रिटेन के संबंध में नकारात्मक टिप्पणी से अटी पड़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों का इस्लामीकरण की शुरूआत अमेरिका समर्थित तानाशाह जिया-उल-हक के सैन्यकाल में हुई। बाद की सरकारें पाठ्यक्रमों में सुधार की बात तो की लेकिन उसे तब्दीली की हिम्मत नहीं दिखा सकी। दरअसल वह मजहबी कट्टरपंथियों और आर्तकियों से डर रही हैं। पाकिस्तानी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के शब्द उड़ेले गए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान का आम जनमानस गैर-इस्लामिक देशों और वहां के निवासियों को घृणा की दृष्टि से देखता है तो अचरज नहीं है। गत वर्ष अमेरिकी संगठन प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तान में हर चार में से तीन नागरिक भारत समेत गैर-इस्लामिक देशों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसका मुख्य कारण स्कूलों में परोसी जा रही जहरीली मजहबी शिक्षा है। एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक 57 फीसद पाकिस्तानी नागरिक भारत और अमेरिका को अलकायदा और तालिबान से भी खतरनाक मानते हैं। उल्लेखनीय यह भी कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों की आवाज बुलंद करने वाले और भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। वे आतंकी और कट्टरपंथी समूहों के निशाने पर हैं। अभी गत वर्ष पहले ही आर्तकियों ने पाकिस्तान के 42 वर्षीय मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उन्होंने अल्पसंख्यक हितों की आवाज बुलंद की। वे चाहते थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उनका वाजिब हक मिले और सरकार ईश-निंदा कानून में बदलाव लाए। लेकिन कट्टरपंथियों को उनकी पहल रास नहीं आई और वे उनकी जान लेकर ही छोड़े। कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाने वाले पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर भी कट्टरपंथियों की क्रूरता से बच नहीं पाए। आर्तकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की विश्वव्यापी आलोचना हुई और पाकिस्तान को अपना बचाव करते हुए कहना पड़ा कि वह दहशतगर्दों से कड़ाई से निपटेगा। लेकिन सच्चाई है कि इस दिशा में उसने आज तक कुछ भी प्रयास नहीं किया। उल्टे वह दहशतगर्दों को संरक्षण ही दे रहा है। नतीजा यह है कि आज कट्टरपंथियों के हौसला बुलंद हैं और वे उदारवादी सोच रखने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली आसिया बीबी को भी कट्टरपंथियों ने मार डाला। भला ऐसे हालात में कोई अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में रहना क्यों चाहेगा? दुर्भाग्यपूर्ण यह कि पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों के पलायन को लेकर तनिक भी फिक्रमंद नहीं है। नतीजा आर्तकियों और कट्टरपंथियों के हौसला बुलंद हैं। गौरतलब यह कि पाकिस्तान निर्माण के समय वहां हिंदुओं की आबादी तकरीबन 15 फीसद थी। लेकिन आज वे एक फीसदी से भी कम रह गए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को खत्म करने के लिए कट्टरपंथी ताकतें दो रास्ते अपना रही हैं। एक उनकी हत्या कर रही है और दूसरा उनका जबरन धर्मांतरण करा रही हैं। नतीजतन वे पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से कट्टरपंथियों और तालिबानी दहशतगर्दों पर कड़ी कार्रवाई न करने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के 65 फीसद भू-भाग पर तालिबानियों का कब्जा है। देखा जाए तो इसके लिए वहां की हुकूमत ही जिम्मेदार है। दुनिया पाकिस्तान को लगातार आगाह कर रही है कि वह अपनी धरती पर कट्टरपंथियों और तालिबानियों को संरक्षण न दे लेकिन वह समझने को तैयार नहीं। हकीकत तो यह है कि जब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर मिलता है, इसका लाभ उठाने के बजाय कट्टरपंथी दहशतगर्दों के पांव सहलाते हैं। ऐसी स्थिति में कट्टरपंथ का बोलबाला क्यों नहीं बढ़ेगा? पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक मुख्य कारण इस्लामिक विचारधारा का उग्र प्रसार भी है। उसी का कुपरिणाम है कि आज पाकिस्तान अपनी ही आग में जल रहा है। बेहतर होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करे। उसे समझना होगा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले से उसकी छवि बिगड़ रही है। दुनिया में संदेश जा रहा है कि नवाज सरकार दहशतगर्दों के साथ है। अगर पाकिस्तान को विश्व बिरादरी में सम्मान हासिल करना है तो उसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और कट्टरपंथियों के फन को कुचलना होगा।

संपादकीय

जासूसी का जाल

बजट सत्र के ठीक पहले केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रालयों में हो रही जासूसी का खुलासा होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेता, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों, रईस उद्योगपतियोंऔर कुख्यात बाहुबलियों का अंतर्जाल देश और समाज की घिनौनी, क्रूर हकीकत है। प्रत्यक्ष में इनके हाथ एक-दूसरे से न मिले हों, लेकिन परोक्ष रूप से सबके हाथ किसी न किसी तरह एक-दूसरे की पीठ पर हैं। समय-समय पर इसकी झलक भी जनता को देखने मिल जाती है। जो सरकार चलाता है वह कहता है कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहींकिया जाएगा। जो विपक्ष में बैठा है वह भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना अपना परम कर्तव्य मानता है। हालांकि दोनों जानते हैं कि भ्रष्ट तरीकों को अपनाए बिना, भ्रष्ट ताकतों को साथ लिए बिना वे अपना स्वार्थ सिद्ध नहींकर पाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार दूर करने का या उजागर करने का दावा करने वालों पर भरोसा कठिन है। आज जब पेट्रोलियम मंत्रालय के कुछ गोपनीय, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी की घटना सामने आई है और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता मिली है, तब यह सवाल उठता है कि जो प्यादे बिसात से उठा लिए गए हैं, क्या उनसे ही भ्रष्टाचार को मात दी जा सकती है या वजीर और राजा तक पहुंच कर उन्हें कभी शह दी जा सकेगी? दस्तावेज चोरी होने का मामला उजागर होते ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने इसकी खुली छूट दी थी, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर बेहद सख्त है। विगत नौ महीनों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, बहुत से चुनावों में उसे करारी हार मिली है, तब इस तरह का बयान देकर श्री प्रधान क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इसका कोई संबंध दिल्ली चुनाव में मिली हार, बिहार के आगामी चुनाव, मोदीजी की छवि को दुरुस्त करने से है? अर्थतंत्र से सीधे संबद्ध मंत्रालयों में जासूसी आज का खेल नहींहै, अरसे से उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ऐसे भ्रष्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं। निचले स्तर से लेकर ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को समय-समय पर कीमती उपहार उद्योग घरानों से पहुंचाए जाते हैं। छुट्टियों के नाम पर विदेशों में ऐश करवाई जाती है। कई बार सरकारी नौकरी से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बड़े अधिकारी निजी कंपनियों में निर्णायक पदों पर बिठा दिए जाते हैं। जाहिर है उनकी सरकारी नौकरी के पूर्व अनुभव ही नहीं, उनकी अंदरूनी पहुंच व संबंध भी उनके लिए लाभदायक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में भ्रष्टाचार का रोना रो कर उन्हें निजी हाथों में सौंपने की वकालत भी इसी भ्रष्टाचार से संबंधित है। सार्वजनिक निकाय गठन के साथ ही भ्रष्ट नहीं हुए, उन्हें खोखला करने में निजी क्षेत्र का षड्यंत्र है, जो सबको नजर आता है, लेकिन कोई कहना नहींचाहता। जहां तक सरकारों या राजनीतिक दलों की बात है तो यह तथ्य भी किससे छिपा है कि इन्हें बड़े पैमाने पर चंदा औद्योगिक घरानों से मिलता है।

चुनावों के वक्त इनके साधनों व संसाधनों का खुलकर उपयोग होता है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबके पीछे औद्योगिक घरानों की पूंजी की ताकत है। इन दिनों वह भाजपा के साथ अधिक दिखती है। चुनावों के वक्त मोदीजी अडाणी लिखे विमान में कितना सफर करते थे, सबको पता है। उन्हें देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री बनाने की कितनी पुरजोर वकालत की थी, यह भी सब जानते हैं। कापोर्रेट पूंजी सामाजिक या देशहित की कितनी भी बातें करे, उसकी पहली प्राथमिकता हर हाल में मुनाफा कमाना होता है, चाहे वह युद्ध के मैदान से ही क्यों न कमाया जाए। ऐसे पूंजीपति अगर अपने लाभ के लिए मंत्रालयों में चोरी करवाते हैं, देशहित से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपि हासिल करना चाहते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए अपने जासूस मंत्रालयों के भीतर पठाए हैं, तो यह आश्चर्य की नहीं, लेकिन चिंता की बात अवश्य है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एक पूर्व पत्रकार समेत रिलायंस, एस्सार आदि के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया का कहना है कि यह घोटाला 10 हजार करोड़ का है। अगर धुआं है तो आग भी लगी ही होगी। सरकार का दावा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। पर यह नीर-क्षीर इंसाफ तो तभी होगा जब हंसों की जमात में शामिल बगुलों की पहचान होगी।

नौ महीनों में जमीनी स्तर पर आया कितना बदलाव

-नीरज कुमार दुबे

पूर्व संप्रग सरकार के नीतिगत फैसले लेने में कथित शिथिलता और भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता में आयी नरेंद्र मोदी सरकार को तब भारी झटका लगा जब एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि पिछले नौ महीने में जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला है और अब कारोबारी अधीर होने लगे हैं। हालांकि पारेख ने यह भी कहा था कि उद्योग जगत मोदी सरकार से अपेक्षित बदलावों को लेकर अब भी आशावान है। जाहिर है देश के बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख हस्ती का यह बयान विपक्ष में जोश भर गया और राजनीतिक दलों ने भाजपा और मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या यह नीतियों की शिथिलता का मामला नहीं है। पार्टी ने कहा कि विरासत के रूप में कई दशकों की अच्छी वृद्धि के बावजूद सरकार के नौ महीने के कार्यकाल के बाद उसके उद्योग जगत के वाहवाही करने वाले लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। ऐसी ही प्रतिक्रिया अन्य विपक्षी दलों की भी रहने पर सरकार को अपने बचाव में आगे आना पड़ा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उद्यमी यह कहना शुरू करेंगे कि ह्यजमीनी स्तर पर बहुत काम हो रहा है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल तो पारेख की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर गये। उन्होंने पूछा कि कहीं उनकी इस टिप्पणी के पीछे कोई व्यक्तिगत वजह तो नहीं है। दरअसल पारेख को कांग्रेस के करीबी के रूप में देखा जाता रहा है लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने समय समय पर संप्रग सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ भी टिप्पणियां की थीं।

संसद के बजट सत्र में संभव है कि पारेख की टिप्पणियां सरकार के लिए मुश्किलों का सबब भी बनें क्योंकि अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार पर लोक लुभावन वादों को पूरा करने का जबरदस्त दबाव भी है। दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से तो सरकार और भी सतर्क हो गयी है। इस पर भी पारेख ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि आम बजट में सुधारों पर ध्यान दिया जाए न कि लोक लुभावन नीतियों पर, दिल्ली में आप की जीत अकेली घटना है और इससे सुधार प्रक्रिया पर आंच नहीं आनी चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि दिल्ली के नतीजों का आर्थिक सुधार प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन बजट भाषण से ही सारी स्थिति साफ हो सकेगी।

पारेख की टिप्पणी को उद्योग जगत की ओर से समर्थन नहीं मिलना सरकार के लिए राहत वाली बात है। वैसे यह हैरत भरी बात भी है कि उद्योग जगत के पथ प्रदर्शक के रूप में देखे जाने वाले पारेख के सुर से अन्य किसी उद्योगपति ने अभी तक अपना सुर नहीं मिलाया है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि समर्थन या विरोध में एक बयान आने के बाद वैसे ही बयानों की लाइन लग जाती है। संभव है उद्योग जगत के अन्य लोगों के मन में आशंकाएं हों लेकिन अभी वह इसे खुले तौर पर जाहिर नहीं करना चाहते हों।

वैसे सरकार और उद्योग जगत के लिए एक राहत की बात यह रही कि देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश उद्योगपतियों ने यह बात स्वीकार की है कि सरकार के ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बात कहने वालों में ऐसे उद्योगपति भी थे जोकि भाजपा सरकार के हर कदम से इत्तेफाक नहीं रखते। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त तथा कुछ अन्य बड़े मंत्रालयों में इस समय ईमानदार मंत्री हैं तथा जहां ईमानदार नहीं हैं वहां लोग प्रधानमंत्री के डर के कारण कुछ ऐसी वैसी मांग नहीं कर रहे। यदि वाकई प्रस्तावों पर मेरिट के आधार पर गौर किया जा रहा है तो यह देश के लिए अच्छी बात है।

इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव और देखने को मिल रहा है। वह यह कि जहां पूर्व की सरकारों के दौरान यह आमतौर पर देखा जाता था कि बिचौलिये तथा लॉबिंग करने वाले लोग मंत्रालयों में आसानी से प्रवेश पा जाते थे और जरूरत के मुताबिक सूचनाएं पाने के बाद ही वहां से रवाना होते थे वैसा माहौल अब नहीं रहा। अब तो मंत्रियों को अपने सचिवों की नियुक्ति की भी आजादी नहीं है, मंत्री के कमरों में आप मोबाइल फोन या पैन तक लेकर नहीं जा सकते। सरकार के बड़े मंत्रियों से मिलना भी अब पहले की तरह आसान नहीं रहा। पूरी छानबीन के बाद ही मिलने का समय दिया जा रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मंत्री को भाजपा मुख्यालय में एक दिन बैठने का जो फरमान सुनाया है उसके बाद से तो मंत्रियों को 'जुगाड़' की चाह में आने वालों को टरकाने का अच्छा बहाना मिल गया है। भाजपा मुख्यालय में मंत्री जब बैठते हैं तो वहां संबंधित मंत्रालय में कोई काम अटका होने के कारण आने वालों के साथ ही संबंधित मंत्रालय से जुड़े अपने उद्योग को लेकर आने वाले उद्योगपति भी सभी के साथ ही बैठते हैं और पूरी बैठक खुले रूप में ही होती है। साथ ही हाल ही में जब पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी कांड का खुलासा हुआ तो यह बात भी सामने आई कि मंत्री को मामले की जानकारी थी और उन्होंने ही इस साजिश का भंडाफोड़ करवाया वह भी तब जबकि कई बड़ी एनर्जी कंपनियां भाजपा और राजग की पक्षधर रही हैं। राजग सरकार भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों के खिलाफ कड़े कदम उठाने में हिचक नहीं रही है इसका एक जीता जागता उदाहरण केंद्रीय गृह सचिव पद से अनिल गोस्वामी को हटाया जाना है। उन्होंने कथित रूप से सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाया था। बहरहाल, यह सही है कि इतने भर से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग जायेगा। भ्रष्टाचार को सिर्फ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर या फिर कानून और कड़ा बनाकर नहीं खत्म किया जा सकता इसके लिए सरकार में शीर्ष स्तर पर ईमानदारी बने रहना जरूरी है। साथ ही फैसले लेने के लिए नौकरशाहों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है क्योंकि ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि अभी भी नौकरशाह सही फैसले लेने में भी हिचक रहे हैं कि कहीं उसमें भी कोई खामी निकालकर उन्हें ना फंसा दिया जाए।

वेलेंटाइन डे से परहेज क्यों

-प्रभाकर चौबे

देश के कुछ संगठन वेलेंटाइन डे से परहेज करने कहते हैं। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी वेलेंटाइन डे पर अपने पद की शपथ ली। सन् 2013 में इसी दिन (14 फरवरी को) उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। इसे संयोग कहा जाए या जानबूझकर उन्होंने 14 फरवरी की तिथि को चुना। त्यागपत्र 14 फरवरी वेलेंटाइन डे और निर्वाचित होने पर 14 फरवरी को ही पद की शपथ लेना। दरअसल 14 फरवरी वेलेंटाइन डे प्यार बिखेरने, प्यार का इजहार करने का दिन है और दुनिया के हर देश में मनाया जाता है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी 14 फरवरी का महत्व जानते हैं और 14 फरवरी को जोरशोर से वेलेंटाइन दिवस मनाने का संदेश दे रहे हैं- उन्हें वेलेंटाइन दिवस पसंद है आगे इसीलिए याद किए जाएं कि वेलेंटाइन दिवस पर उन्होंने पद की शपथ ली थी।

वेलेंटाइन दिवस से चिढ़ किस बात की? इसका विरोध क्यों किया जाना चाहिए? लेकिन विरोध किया जा रहा है, किया जाता है। हर साल वेलेंटाइन दिवस के पूर्व कुछ संगठन विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक सप्ताह पूर्व ही विरोध शुरू हो जाता है। विरोध के कारण भी वेलेंटाइन दिवस पापुलर हो गया है। वैसे विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है या मनाने वालों की, इसका आकलन किया जाए तो वेलेंटाइन दिवस के पक्ष में ज्यादा मत पड़ेंगे। विरोध करने वाले लाख विरोध करते रहें, एक बड़ा वर्ग इस विरोध को पसंद नहीं करता। इसका एक कारण तो यह है कि अपना देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में लोगों की आस्था मजबूत हुई है। अपनी मनपसंद की पार्टी को निडर होकर वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है और 65 वर्षों से जनता अपने अधिकार का प्रयोग करते आ रही है। अपने वोट की ताकत से जनता ने सरकारें बनाईं और जिस पार्टी की नीतियां पसंद नहीं आईं उसे सत्ता से बाहर भी कर दिया गया। लोकतंत्र में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है इसलिए जिस पार्टी में सत्ता का अहंकार उपजा, बढ़ा, उस पार्टी को जनता ने सबक सिखाया, यह सब हमारे सामने है। दिल्ली में भाजपा को जनता ने ही सत्ता में आने से रोका। इसी माह यह हुआ। भाजपा को अतिविश्वास ने दबोच लिया था- खुद को अपराजेय समझने लगी थी भाजपा। जनता को उसकी कथनी और करनी में भेद स्पष्ट दिखाई पड़ा और जनता ने उसे सत्ता में आने नहीं दिया। मतलब लोकतंत्र ने जनता को ताकतसम्पन्न किया है। जनता को विश्वास से भरा है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सजा भोग रही है। वामदल अभी स्थिति पर चिंतन कर रहे हैं। भाजपा खूब ऊंचा चढ़ी, दिल्ली में नीचे ला दी गई। कहने का तात्पर्य यह कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी का पर्व, त्योहार, उत्सव, दिवस मनाए। यह सामंती काल नहीं है, लोकतंत्र है। अब राजा-महाराजा, सम्राट, बादशाह, नवाब, किसी का राज नहीं है। वे रहे भी नहीं। सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और एक ही संविधान के तहत अपना काम कर रहे हैं इसलिए वेलेंटाइन डे का विरोध अब नहीं करना चाहिए। समाज अगर वेलेंटाइन डे मना रहा है तो मनाने दिया जाए। डराने, धमकाने, भय पैदा करने की मानसिकता पर रोक लगे। सब को लोकतांत्रिक ढंग से अपना उत्सव मनाने की सुविधा मिले, यह शासन को देखना चाहिए। राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि वे लोगों को आचरण, व्यवहार में शिक्षित-दीक्षित करें। वेलेंटाइन डे का विरोध क्यों किया जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति कहकर इसका विरोध किया जाता है। आश्चर्य है कि आज ग्लोबल युग में ऐसे समय जबकि विश्व-ग्राम की बात हो रही है, ग्लोबल विलेज को लेकर भारत भी उत्साहित है, तब किसी पर्व, किसी त्योहार, किसी दिवस को पाश्चात्य संस्कृति कह कर उसका विरोध किया जाए। आज वेलेंटाइन डे पाश्चात्य कैसे और क्यों हो गया। वेलेंटाइन डे भारत में आकर भारतीय हो गया- यह ग्लोबल है और भारत उस विश्व का हिस्सा है इसलिए वेलेंटाइन डे भारत में मनाया ही जाएगा इससे बचा नहीं जा सकता। विदेशों में होली, दिवाली मनाने के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। अगर वेलेंटाठन डे पाश्चात्य संस्कृति है तो हम पश्चिम से आए किस-किस रस्मों-रिवाजों, व्यवहारों का विरोध करें। उन्हें अपने जीवन व्यवहार से अब हम नहीं निकाल सकते। हमारे व्यवहार हमारे सम्बोधन का हिस्सा बन चुके कई शब्द हैं। पिछली बात न करें, आज की बात कहें- मोबाईल कहां से आया। उसे हमने किस तरह अपना लिया और "मिस काल" का अनुवाद किसी भी भाषा में करना अटपटा ही लगेगा। मजदूरी करने वाले भी कहते हैं- "एक मिस काल मार देबे।"

आज स्वदेशी-विदेशी का भेद खत्म हो गया है। हम सुस्त चलने वाली दुनिया से निकलकर रफ्तार की दुनिया में आ गए हैं। आज की पीढ़ी आज के अनुसार जीना चाहती है और वैसा ही जीवन जीयेगी, वैसा ही व्यवहार करेगी। आज की पीढ़ी अपना संसार बना रही है। "अपना लोक" गढ़ रही है। वेलेंटाइन डे का विरोध आधुनिकता को पीछे खींचना है। जहां तक शालीनता से मनाने कहने की बात है तो हर त्योहार शालीनता से मनाना चाहिए दिवाली पर पटाखा फोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए। होली को शालीनता से मनाने की अपील की जाती है। वैसे हमारी फिल्मों में प्यार के इजहार के लिए नदी किनारे, सरोवर के तट पर, समुद्र किनारे, बसों, रेल के डिब्बों, बाग-बगीचों, सड़कों पर दौड़ते हुए ही नायक-नायिका गाते दिखलाए जाते हैं। कुछ ही गीत कमरे में बैठकर गाए जाते दिखाये गए हैं। प्रायः रोने के लिए गाए जाने वाले गीत कमरों में गाए जाते हैं। वेलेंटाइन डे प्यार के इजहार का दिवस है अतः बाग-बगीचों में, पिकनिक स्पाट में, होटलों में यह मनाया जाएगा। वेलेंटाइन डे को बाजार ने बढ़ाया, पापुलर किया, यह भी आरोप लगाया जाता है। सोचने की बात है कि जहां पूजा स्थल है आस-पास दुकानें लग जाती हैं। धार्मिक नगरों में मंदिर के सामने विविध दुकान होते हैं। दर्शन के बाद खरीदारी होती है। अब तो तरह-तरह के मुहूर्त दर्शाकर लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा है और समाचार पत्रों में तत्संबंधी विज्ञापन प्रकाशित भी होने लगे हैं। जिन विशेष मुर्हूत की शुभ नक्षत्र की जानकारी ही नहीं थी अब विज्ञापनों के द्वारा उनकी जानकारी दी जा रही है और बाजार में उन खास मुहूर्तों पर भीड़ होने लगी है इसलिए वेलेंटाइन डे को बाजार ने बढ़ाया हो तो हर्ज क्या है। व्यापार अपना रास्ता तलाश लेता है। मूल बात यह कि वेलेंटाइन डे का विरोध न कर इसे उन लोगों को खुशी के साथ मनाने दिया जाना चाहिए जो मनाना चाहते हैं। आज हर घर में मां को मम्मी, पिता को डैड कहने का रिवाज चला है, स्वीकार भी कर लिया गया है। कुछ लोग तो बाबूजी की जगह डैड कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हर उम्र का व्यक्ति अंकल और हर उम्र की महिला आंटी हो गई है। लोग कह रहे हैं। लोग सुन रहे हैं। युगानुरूप सम्बोधन चलते हैं। जबरन कुछ नहीं चलाया जा सकता। वेलेंटाइन डे अगर आ गया है, चलन में शामिल हो गया है तो वह अब रुकेगा नहीं, चलेगा। चलने भी दें। अगर बाजार को फायदा होता है तो होने दें, कुछ को रोजी-रोटी मिल रही है। तनाव पैदा करना लोकतांत्रिकता को नुकसान पहुंचाना और कुछ अर्थों में उसे धमकाना भी है। वेलेंटाइन डे किसी भी संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नयी पीढ़ी बहुत लोकतांत्रिक और सूझ-बूझ वाली है। कुछ सरकारें वेलेंटाइन डे को "मातृ-पितृ" दिवस के रूप में मनाने कहती हैं और विद्यालयों में आयोजन किए जाते हैं। यह बात जमती नहीं। वेलेंटाइन डे पर वेलेंटाइन डे ही मनेगा। मातृ-पितृदिवस अलग है। वैसे आज की पीढ़ी "फादर्स डे", "मदर्स डे", " ग्रैंड फादर्स डे", "ग्रैंड मदर्स डे" मना रही है- यह अच्छा लगता है। नये पर्व हैं चलेंगे। व्रत, पर्व, त्योहार का अपना महत्व है।

राष्ट्रीय संस्करण, आर.एन.आई. संख्या डीईएलएचआईएन2005/16576

स्वामी, मुद्रक, संपादक एवं प्रकाशक मो. सिराज 'साहिल' द्वारा एसएस प्रिंटर, 201, यूके II ईकोटेक 3, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.) से मुद्रित और सरोकार, प्रताप भवन, चतुर्थ तल, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित।

संपादक : मो. सिराज 'साहिल'*

कार्यकारी संपादक : संजय सचदेव

प्रबंध संपादक : बरखा अरोड़ा

मो. 9958449947, 9211422329, 9717743739, 9250334541, 9250334542

टेलीफैक्स : 011-43518682 **ई-मेल- editor.sarokar@gmail.com, sarokar@sarokar.com एवं editor@sarokar.com**

*पीआरबी अधिनियम के अनुसार समाचार चयन और संपादन के लिए उत्तरदायी।

नोट : समाचार पत्र से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा।